Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 08, Issue-II, Oct. 2022

भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
(Internal Security Challenges Before India: An Analytical Study)

Anil Singh [a,*]
[a]*Assistant Professor, Law Department, M.M.H. College, Ghaziabad, Chaudhary Charan Singh University Meerut, U.p., (India).*

KEYWORDS
सुरक्षा और चुनौतियॉ, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, देश की रक्षा प्रणाली, आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, संगठित अपराध, एकता और अखण्डता सुनिश्चित करना

ABSTRACT
किसी भी देश की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा व्यवस्था होती है, चाहे सुरक्षा बाहरी खतरों से हो या आंतरकि खतरों से। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि वह बाहरी एवं आंतरकि दोनों ही दृष्टि सशक्त एवं सुदृण हो। जितनी आवश्यक देश की बाहरी खतरों से सुरक्षा है उससे कहीं अधिक आवश्यक है आंतरकि सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य है देश की सीमाओं के भीतर शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए देश की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता सुनिश्चित करना है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस से लेकर अर्द्धसैनिक बलों तक और असाधारण परिस्थितियों में सेना की हो सकती है। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व केन्द्र एवं राज्य दोनों के रक्षा क्षेत्र में आता है। भारत एक विशाल देश है यह अनेक विविधताओं वाला देश है जिसमें अनेकों जातियाँ, धर्म, भाषायें तथा क्षेत्रीय विषमतायें है, जिससे देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। देश की इन्ही विविधताओं एवं विषमताओं के चलते शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करना मुश्किल भरा कार्य है। भारत जैसे विशाल देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को लेकर काफी गम्भीर स्थिति बनी हुई है, ऐसी अनेकों समस्यायें हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती देती आ रहीं हैं, जिसमें मुख्य चुनौतियों के रूप में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, संगठित अपराध, लगातार बढ रही क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति, शांतिपूर्ण आन्दोलनो का उग्र रूप धारण करना जिसके साथ ही साइबर अपराध, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेक न्यूज जैसी नयी–नयी उभरती चुनौतियाँ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बडा संकट पैदा कर रहीं है।

प्रस्तावना

किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को संकट दो तरह से हो सकता है एक बाह्य दूसरा आंतरिक। देश को सुरक्षित तभी कहा जा सकता है जब वह दोनों ही तरह के संकटो से पूर्णतः सुरक्षित हो। दोनों ही संकटों से तभी निपटा जा सकता है जब देश की रक्षा प्रणाली मजबूत एवं सुदृण हो। देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए बाह्य सुरक्षा के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी तो देश बाह्य खतरों से भी निपटने में सक्षम होगा, यदि आंतरिक सुरक्षा कमजोर पडती है तो देश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा देश की एकता एवं अखण्डता पर लगातार खतरा बना रहेगा। आंतरिक सुरक्षा की कमजोरी देश को अन्दर से दीमक की तरह खोखला कर रही है और इस बढती हुई समस्या को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा की मजबूती नितान्त आवश्यक हो जाती है। 71 वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के विकास के लिए एक सुदृण आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का होना जरूरी है।[1]

''आंतरिक सुरक्षा एक सम्प्रभु राज्य या अन्य स्वशासित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर शान्ति बनाये रखने का कार्य है, जो आमतौर राष्ट्रीय कानून को बनाये रखने और आंतरिक सुरक्षा के खतरों के खिलाफ बचाव के द्वारा होता है।[2] आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य दोनों के क्षेत्र का प्रश्न है जिसमें इस जिम्मेदारी को निभाये जाने का दायित्व पुलिस से लेकर अर्द्धसैनिक बलों तथा बिशेष परिस्थितियों में सेना का हो सकता है। श्री पी. चिदंबरम ने भी कहा है कि देश की सुरक्षा केन्द्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।[3] राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आन्तरिक सुरक्षा का प्रबंधन देश के लिए एक प्रमुख चुनौती बनने जा रहा है, आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन किए बिना भारत एक शक्तिशाली एवं महान देश नहीं बन सकता, पुलिस बल को अदृश्य दुश्मन के साथ चौथी पीढ़ी की जंग में मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होना

Corresponding author
***E-mail:** anilsingh281982@gmail.com (Anil Singh). https://orcid.org/0000-0002-3558-729X
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v8n2.04
Received 07th October 2022; Accepted 20th October 2022; Available online 30th Oct. 2022
2454-8367 /©2022 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

चाहिए।[4]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्या का बीजारोपण देश के विभाजन के दौरान ही हो गया था, जब देश धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित हो गया, जिसके पश्चात पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठनों द्वारा जम्मू–कश्मीर तथा आस–पास के क्षेत्रों में लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

राज्यों के आपसी विवादों एवं भाषाई उपद्रवों के कारण 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1950 के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति पर आधारित अशांति फैली, इन राज्यों से अन्तर्राज्यीय सीमा सम्बन्धी विवाद बार–बार सामने आ रहे हैं।

1960 के दशक में पश्चिम बंगाल से नक्सलबाद का उदय हुआ, 1980 के दशक में पंजाब में सिख आन्दोलन, कश्मीर में अलगाव वादी संगठनों द्वारा उग्रवादी आन्दोलन की शुरूआत तथा वर्तमान समय में शान्तिपूर्ण आन्दोलनों का उग्र रूप धारण करना, धर्म एवं जातीय आधारित दंगों तथा सरकार विरोधी गतिविधियों जैसी घटनाओं ने देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष गम्भीर समस्यायें उत्पन्न कर रखी है।

मुख्य चुनौतियाँ

देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अनेकों चुनौतियाँ बाहें फैलाये हुए है परन्तु कुछ मुख्य चुनौतियाँ देश की आजादी एवं विभाजन के समय से ही लगातार खतरा बने खडी हुईं हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं– 1. परम्परागत चुनौतियाँ 2. नवीन चुनौतियाँ।

क्र. सं.	परम्परागत चुनौतियाँ	क्र. सं.	नवीन चुनौतियाँ
1.	आतंकवाद	1	सइबर अपराध
2.	नक्सलवाद	2	मीड़िया
3	संगठित अपराध	3	सोशल नेटवर्किंग
4	साम्प्रदायिकता	4	हाईब्रिड या अंश कालिक आतंकवादी
5	उत्तर–पूर्वी राज्यों में उग्रवाद		
6	मादकद्रव्य व्यसन		
7	बाल अपराध		

आतंकवाद

आतंकवाद बाह्य एवं आंतरिक दोनो प्रकार की सुरक्षाओं के लिए सबसे बडी चुनौती है, आतंकवाद ने भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखीं हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए जगह–जगह बम विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर सरकार एवं जनता के बीच डर एवं भय का माहौल उत्पन्न कर दिया जाता है जिससे मानव जीवन की असुरक्षा का भय बना रहता है। आतंकवादी गतिविधियों के चलते जान माल की क्षति तो होती ही है साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंधन भी होता है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने राष्ट्रीय जाँच ऐजेंसी के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों के उल्लंधन का सबसे बड़ा रूप है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना नितांत आवश्यक है।[5]

भारत में आतंकवाद की समस्या भारत विभाजन के साथ ही उत्पन्न हो गयी थी। आज देश की सीमाओं के भीतर सैकड़ों आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं जो समय–समय पर भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में बम विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं जिनमें से सरकार द्वारा कई आतंकवादी संगठनों को विभिन्न कानूनों के माध्यम से प्रतिबंधित भी किया गया है। मुम्बई सीरीयल बम ब्लास्ट, संसद भवन पर आतंकी हमला, अक्षरधाम मंदिर हमला, पठानकोट एयरबेस हमला, पुलवामा अटैक जैसी घटनाओं को आतंकी संगठनों द्वार लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर तो आतंकवाद का जैसे गढ़ ही बन गया हो। जम्मू कश्मीर में घरेलू आतंकवाद की घटनायें आंतरिक सुरक्षा के लिए जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहीं हैं। उग्रवादी तथा अलगाववादी संगठनों द्वारा लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों द्वारा आम नागरिकों की हत्या, सुरक्षा बलों पर आतंकीयों तथा पत्थरबाजों द्वारा हमले आम बात हो गयी है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले धार्मिक कट्टरता एवं क्षेत्रवादी प्रवृत्ति की देन है। जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कुछ कमी आयी है। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि केन्द्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों की संख्या घट रही है लेकिन हिंसा का अंत तब तक नहीं होगा जब तक युवाओं के हाथों में बंदूक तथा हथगोला होगा।[6]

नक्सलवाद

भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, जो 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी। प्रारम्भ में नक्सलवाद स्थानीय जमींदारों के विरूद्ध एक किसान आंदोलन था, यह आंदोलन चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल के नेतृत्व में शुरू हुआ जो चीनी क्रान्तिकारी माओत्से तुंग के विचारों से प्रेरित था।[7] जिसने बाद में उग्र रूप धारण कर लिया और आस–पास के क्षेत्रों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, बिहार, ओड़िसा में बहुत तेजी से फैला। 1972 में चारू मजूमदार की गिरफ्तारी तथा मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ गया।[8] 2004 में नक्सलियों अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या हमारे देश के सामने अब तक की सबसे बड़ी आंतरकि सुरक्षा चुनौती है।[9] सरकार द्वारा नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाये जिनके तहत कई नक्सली संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबन्धित कर दिया और सामाजिक–आर्थिक विकास की रणनीति को प्राथमिकता दी। 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल बंदूकें और गोलियां इस दशकों पुरानी समस्या का समाधान नही कर सकती केवल विकास ही एकमात्र रास्ता है।[10]

संगठित अपराध

संगठित अपराध एक ऐसा अवैध कार्य है जो दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से किया जाता है। अक्सर लोग अपनी अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए अपने औपचारिक या अनौपचारिक संगठनों का निर्माणकर लेते हैं। इन

संगठनों का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार द्वारा या डरा धमकाकर अवैध कार्यकलापों के माध्यम से धन अर्जित करना होता है। इस प्रकार के संगठनों द्वारा व्यक्तियों को कोई ऐसी सेवा या वस्तु उपलब्ध करायी जाती जो अवैध एवं कानून द्वारा प्रतिषिद्ध हो तथा जो आसानी से उपलब्ध न हो सके। इस प्रकार के संगठन एक रैकेट के रूप में कार्य करते हैं जैसे हिंसक आपराधिक संगठन, आपराधिक सिंडीकेट, आपराधिक रेकेट्स, राजनीतिक उत्कोच।[11] ऐसे संगठनों का संचालन कुश ल एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के संगठन हर क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के संगठन आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।

साम्प्रदायिकता

हमारा देश अनेक विविधताओं का देश है यह एक धर्म निरपेक्ष राज्य है जहां कई धर्मों के लोग वास करते हैं जहां सभी घर्मों के साथ समान वयवहार किया जाता है।[12] परन्तु जहां धर्म का प्रश्न हो वहां टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और यह टकराव हिंसा में बदल जाता है। साम्प्रदायिक हिंसा किसी विशेष सम्प्रदाय, धर्म या जाति को निशाना बनाकर की जाती है जिससे उस धर्म या सम्प्रदाय विशेष में समाज के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। देश में बढ़ रहे साम्प्रदायिक दंगों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को कड़ी चुनौती पेश की है। सम्प्रदायिक हिंसा की प्रमुख घटनायें जैसे 1984 में सिख विरोधी दंगे, कश्मीर से कश्मीरी पण्डितों को भगाया जाना, बाबरी मस्जिद विवाद, गुजरात दंगे, ये ऐसी साम्प्रदायिक घटनायें हैं जिन्होने देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया।

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद

जम्मू–कश्मीर के बाद उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे अधिक चुनौती पेश करता है। उत्तर पूर्वी भारत में आठ राज्य शामिल हैं, असम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, जहां उग्रवादी संगठनों द्वारा लगातार हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों से खराव शासन, विकास की कमी, सरकार की उदासीनता जैसे मुद्दों पर सरकार विरोधी विद्रोह के जरिए स्वायत्ता की मांग की जाती है। उत्तरपूर्वी राज्यों में उग्रवादी घटनायें भाषाई, जातीय एवं क्षेत्रवादी प्रवृत्ति पर आधारित हैं। वर्तमान समय में इन राज्यों में उग्रवादी घटनाओं में कुछ कमी आई है जो संतोश जनक स्थिति है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से सम्बंधित घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी आयी है।[13]

मादक द्रव्य व्यसन

मादक द्रव्य व्यसन आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है। नशे की लत के कारण आज युवा अपना तथा देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही देश की सुरक्षा के समक्ष मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जिससे देश की युवा पीढ़ी की रगों में जहर घुल रहा है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी तथा बेरोजगारी के चलते हताशा एवं निराशा के कारण युवा वर्ग अपनी हताशा को कम करने के लिए नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं जिससे वे नशे के आदी हो जा रहे हैं तथा अपनी इस नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ उग्रवादी संगठन तथा गिरोह इनके हाथ मे बम तथा बंदूकें थमा देते हैं और नशे की लत में जकड़े ऐसे व्यक्ति अपनी इस लत के वशीभूत आतंकी संगठनों में शामिल होकर देश तथा जनता में भय तथा आतंक का माहौल उत्पन्न करने के लिए हिंसक घटनाओं, दंगों, बम बिस्फोट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि जम्मू के युवा नशे की लत के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कश्मीर में हताश युवा आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं।[14]

बाल अपराध की समस्या

देश के अंदर बाल अपराधियों की संख्या का लगातार बढ़ना चिंता का बिषय है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। सामान्यतः किसी बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराधी एक निश्चित आयु सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18 बर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है जिसके अन्तर्गत भीख मांगना, आवारागर्दी करना, गलत इरादे से शैतानी तथा दुर्व्यवहार भी शामिल है।[15] बाल अपराधियों द्वारा सबसे अधिक हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। यही बाल अपराधी आगे चलकर समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थता के चलते आदतन अपराधियों का साथ पाकर बड़े अपराधी बन जाते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 2(12),एवं धरा 2(13) में कहा गया है कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक से अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।[16] ऐसे अपराधियों पर अक्सर उग्रवादी संगठन तथा गिरोहों का हाथ होता है क्योंकि बाल अपराधों के पीछे समाज, परिवार, गरीबी तथा नशे की लत जैसे कारण हाते हैं तथा ऐसे अपराधियों के दिमाग को परिवर्तित कर उनमें समाज तथा देश के खिलाफ आसानी से भड़काकर हिंसात्मक आंदोलनों, जातीय तथा धार्मिक दंगों को भड़काने में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

नवीन चुनौतियांः–

जेसे–जैसे देश विकास के मार्ग पर रफ्तार पकड़ता गया, नई–नई समस्याओं का जन्म होता गया या यूँ कहें विकास ही सबसे बड़ी समस्या बन गया और देश की आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष नई–नई चुनौतियां उत्पन्न होती गयी। वर्तमान समय में विकास और समस्यायें साथ साथ चल रहीं हैं जो निम्नलिखित हैं–

साइबर अपराध–

किसी भी देश के विकास के लिए प्रोद्योगिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में भी विकास आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बिना प्रोद्योगिकी देश का विकास असम्भव सा प्रतीत होता है। देश में प्रोद्योगिकी एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास के साथ साथ साइबर अपराध जैसी नई समस्यायें भी उत्पन्न हुयी हैं जैसे कम्प्यूटर हैकिंग, डाटा चौरी, धोखा धड़ी, साइबर युद्ध, ब्लैकमेलिंग,

इलेक्ट्रोनिक फार्म में अश्लील जानकारी का प्रकाशन जैसी आपराधिक गतिविधियों को साइबर अपराधी बखूवी अंजाम दे रहे हैं जो देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि साइबर जगत में हो रहे अपराधों में हर साल 21 प्रतिशत की बृद्धि हो रही है।[17] उन्होने सुरक्षा बलों से कहा कि सुरक्षा बल भविष्य की इस बड़ी चुनौती के लिहाज से स्वयं को तैयार करें, साथ ही उन्होने सीईआरटी–इन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कम्प्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से साइबर अपराध भी बढ़ रहा है, उन्होने साइबर दुनिया में उग्रवादी एवं आतंकी गुटों की हरकत को लेकर सुरक्षा बलों को आगाह किया।[18]

मीड़िया

वैसे तो मीड़िया देश की शासन व्यवस्था का चौथा स्तम्भ कहलाता है। मीड़िया के जरिए हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मीड़िया विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है।[19] परन्तु वर्तमान समय में मीड़िया ही अपराध का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है जो अपराधियों को अपराध की नई नई तकनीकों का ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मीडिया द्वारा मो. अजमल मो. आमिर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र राज्य[20] के मामले में ताज होटल, होटल ओबराय तथा नरीमन हाउस पर आतंकवादी हमले को लगातार टी.वी. चैनलों पर दिखाये जाने से यह स्थिति पैदा हो गयी कि आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की हर स्थिति की जानकारी मिल रही थी जिस बजह से परिस्थितियों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आजकल मीडिया जगत में पेड न्यूज अपने पैर पसार चुका है जिससे भ्रष्टाचार जैसे अपराधों को बढ़ाबा मिल रहा है। पेड न्यूज की वजह से जनता तक सही सच्ची खबरें नहीं पहुंचती और गलत खबरों तथा अफवाहों के चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे असामाजिक तत्वों को अपराध करने का अवसर प्राप्त होता है, और यह स्थिति देश की आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती के रूप में उभर रही है।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स

सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों के आपसी सम्पर्क तथा समाज को आपस में एक दूसरे से जोडने का सबसे सरल एवं सुगम माध्यम है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही व्यक्तियों एवं समाज के आपसी रिस्तों को जोडे हुए हैं। परन्तु अब इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का गलत इस्तेमाल होने लगा है जो अब असामाजिक तत्वों के हाथों का खिलोना मात्र बन कर रह गयीं हैं, जिससे यह साइट्स आपराधिक गतिविधियों के संचालन में सहायक सिद्ध हो रहीं हैं। इन नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से सरकार विरोधी एवं फेक न्यूज जैसी गतिविधियों से जातीय एवं धार्मिक दंगे, शान्तिपूर्ण आन्दोलनों को हिंसात्मक रूप प्रदान करना अब बहुत आसान बन गया है। अब सुविधा ही समस्या बन गयी हैं जो देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती पेश कर रही हैं।

हाईब्रिड या अंश कालिक आतंकवादी

वर्तमान में कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाईब्रिड नामक एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।[21] हाईब्रिड या अंश कालिक उग्रवादी वे लोग होते हैं जो पेशेवर आतंकी नहीं हैं और पुलिस रिकॉर्ड में उग्रवादी के रूप में नहीं आते हैं। ये वे लोग होते हैं जो नौकरी या व्यवसाय करते हैं और कभी कभार आतंकवादी गतिधियों में शामिल होते हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर सामान्य जीवन में वापस आ जाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनका तथा उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।[22] 23 मई 2022 को श्रीनगर पुलिस ने लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े दो स्थनीय हाईब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।[23]

आंतरिक सुरक्षा के खतरों के कारण

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों के अनेक तथा विभिन्न कारण हो सकते हैं परन्तु कुछ कारण जो प्रत्यक्ष होते हैं हम उन कारणों का अध्ययन कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं–

सामाजिक कारण

व्यक्ति स्वभावतः अपराधी नहीं होता परन्तु समाज की विषम परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है जब वह समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहता है तब उसमें असंतोष तथा हताशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, यही हताशा एवं असंतोष की भावना उसे अपराध की ओर अग्रसर करती है। इन घटनाओं के पीछे उसकी संगति का बहुत असर होता है, जिसमें निश्क्रिय समूहों की सदस्यता, अंतःक्रियात्मक समूहों की सदस्यता तथा व्यक्तिगत मित्रता भी सम्मिलित है। अक्सर समाज से विमुख व्यक्ति अपराध का रूख कर लेता है। इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न अपराधी अपने अवैध क्रियाकलापों के माध्यम से देश में कानून तथा शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ऐसे अपराधी समाज से घृणा तथा प्रतिशोध की भावना के चलते उग्रवादी एवं आतंकी संगठनों एवं गिराहों में सम्मिलित होकर उग्रवादी एवं आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा शान्तिपूर्ण आंदोलनों को हिंसक तथा उग्र रूप प्रदान कर देश की एकता एवं अखण्डता तथा शान्ति व्यवस्था को क्षति पहुचाते हैं।

आर्थिक कारण

कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आर्थिक दशायें देश तथा समाज में बर्ग संघर्ष को जन्म देतीं हैं।[24] यही वर्ग संघर्ष देश में भेदभाव तथा अराजकता का कारण बनता है। पूँजीवादी व्यवस्था के चलते अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जाता है। आज के समय में वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए नहीं अपितु लाभ के लिए होता है वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि, मंहगाई दर का लगातार बढ़ना तथा एवं बेरोजगारी जैसे कारण समाज के निचले वर्ग के युवाओं में हताशा, निराशा तथा रोष उत्पन्न करते हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की असमर्थता के कारण अपराध का रूख कर बैठता है ओर अपनी तथा परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे गरीब, मजबूर, और लाचार व्यक्ति देश के दुश्मनों के हाथों बिक कर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करते हैं तथा देश की शान्ति व्यवस्था को भंग करते हैं।

राजनीतिक कारण

राजनीतिक परिस्थितियां आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरों के कारणों में बहुत हद तक अपना योगदान करती हैं। अक्सर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों को भड़काया

जाता है। देश तथा समाज के प्रति सरकार की नीतियों के खिलाफ अक्सर आंदोलन तथा विद्रोह होते रहते हैं जिसका जीवित उदाहरण दिल्ली में किसान आंदोलन तथा सी.ए.ए. तथा एन.आर.सी. के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में विरोध प्रदर्शन को हिंसात्मक विद्रोह में बदल दिया। अक्सर इस प्रकार के राजनीतिक दल अपने स्वार्थ तथा सत्ता प्राप्ति की चाह में देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं, साथ ही देश को अनचाहे हिंसात्मक आंदोलनों के बीच धकेल रहे हैं।

अशिक्षा

शिक्षा देश के युवाओं का भविष्य तथा उन्हें जागरूक तथा आत्मनिर्भर बनाती है। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह देश के विकास में अपना योगदान करे परन्तु देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षा के कारण देश तथा समाज के विकास की रफ्तार में अशिक्षा के करण पिछड़ता जा रहा है। अशिक्षा के चलते ही ऐसे वर्ग, हाथों में हथियार लेकर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करते हैं।

धार्मिक तथा जातिय कारण–

धार्मिक कट्टरता तथा जातिय भेदभाव देश में दंगे, हिंसात्मक आन्दोलन, उन्माद फैलाने में तथा देश की शान्ति व्यवस्था को खत्म करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं।

निष्कर्ष

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों और उसके कारणों का अध्ययन करने के पश चात यह प्रतीत होता है कि समस्यायें भिन्न–भिन्न तथा जटिल हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद तथा उग्रवाद आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अभियानों को योजनाओं को समय समय पर क्रियान्वित किया गया है, जिसमें सरकार को बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है, जो कि एक संतोषजनक सिथिति है। परन्तु कुछ बातों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाय तो समस्याओं पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है–

1. आतंकवाद जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करना केवल किसी एक राज्य या देश के बस की बात नहीं है। चूंकि यह पूरे विश्व की समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा अर्थात् आतंकवाद को खत्म करने के लिए अन्तर्राष्ट्रय सहयोग आवश्यक है।
2. देश में उग्रवाद तथा नक्सलवाद जैसी समस्यायें लोगों की आधारभूत जरूरतों, गरीबी, बेरोजगारी, खराव शासन व्यवस्था, तथा समाज से अलगाव के चलते उत्पन्न हुयीं। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास योजनायें चलाकर इन क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाये।
3. व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है समस्यायें भी वहीं जन्म लेती हैं। भटके हुए अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता कर उसे अपराध मार्ग त्याग कर संमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे अपराधों में कमी आयेगी तथा श न्ति व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी।

जैसी समस्याओं ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है जिनके चलते आतंकवाद, उग्रवाद तथा नक्सलवाद जैसी गतिविधियों में बहुत हद तक कमी देखने को मिली है। हाल ही में प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्ष 2020 के दौरान देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही, सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उचित प्राथमिकता दी है, और इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है।[25] परन्तु असम के कोकराझार में एनडीएफबी–एस के उग्रवादियों द्वारा 14 लागों की गोली मारकर हत्या करना तथा जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है।[26] अगर देखा जाय तो उग्रवाद तथा नक्सलवाद ऐसी समस्यायें हैं जिनकी जड़ें काफी गहरी हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये समस्यायें एक रात, एक दिन या महीने भर में खत्म होने वाली नहीं हैं, इनका इतिहास बहुत गहरा तथा खून से भरा हैं, ये लड़ाई अभी काफी लम्बी चलेगी। इसके अलावा देश के समक्ष नई नई समस्याओं ने भी अपने पाँव पसारने शुरू कर दिये है, जिससे चुनौतियां और कड़ी हो गयी है, जिन्होंन देश की आन्तरिक सुरक्षा को लेकर सरकार की नींद उड़ा रखी हुई है।

सुझाव

1. विकास के बढ़ते दौर में संचार माध्यमों जैसे सोशल मीड़िया तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्वीटर, वॉट्सअप, इंस्टाग्राम आदि जिनके द्वारा आज अपराधों को गति मिल रही है के इस्तेमाल करने के लिए कड़े कानूनों का निर्माण कर इस समस्या को और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।
2. देश में बढ़ती हुई मंहगाई दर, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर इन समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
3. आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, साम्प्रदायिकता, संगठित अपराध, साइबर अपराध जैसी अवैध गतिविधियों के लिए पोटा, टाड़ा, यूएपीए, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, मकोका तथा रासुका जैसे कानूनों को सरकार द्वारा सख्ती से लागू कराया जाय।

उपरोक्त बिंदुओ के माध्यम से देश में कानून तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा देश में एकता और अखण्डता बनाये रखने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

संदर्भित सूची

[1] Sujeet Kumar Upadhyay, राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधनः सरकार नें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उठाए ठोस कदम, January 25, 2020, 7:47 PM IST, Last Seen December 19, 2020, https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/president-ram-nath-kovind-addressing-nation-government-took-concrete-steps-to-strenthen-internal-security-3921280/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/internalsecurity

[3] भाषा, आंतरिक सुरक्षा केंद्र व राज्य की साझा जिम्मेदारी: चिदंबरम, 18 फरवरी 2012, 2:58 PM IST, Last Seen December 19, 2020, https://www.aajtak.in/trending/story/countrys-a-shared-responsibility-chidambaram-11499-2012-02-18

[4]आंतरिक सुरक्षा होने बाली है भारत की सबसे बड़ी चुनौती: डोभाल, oct 31, 2015, 11:06 PM IST, Last Seen May 07, 2022, https://zeenews.india.com/hindi/india/internal-security-key-to-become-global-power-ajit-doval/274570

[5]PTI, Terrorism Biggest Form of Human Rights Violation: Amit Shah, April 21, 2022" 04:12 PM IST, https://m.economictimes.com/news/india/terrorism-biggest-form-of-human-rights-violation-amit-shah/articleshow/90974780.cms

[6] भाषा, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटे, लेकिन जब तक बन्दूक है हिंसा खत्म नहीं होगी: डीजीपी सिंह, March 25, 2022, 05:14 IST, https://ndtv.in/india-news/terrorists-have-decreased-in-jammu-and-kashmir-but-violence-will-not-end-as-long-as-there-is-a-gun-dgp-singh-2841922

[7] https://globalsecurity.org/military/world/war/naxalite.htm

[8]Niranjan Sahoo, Half a Century of India" s Maoist Insurgency: An Appraisal of State Response, 13 June 2019, Last Seen May 05, 2022, https://www.orfonline.org/research/half-a-century-of-indias-maoist-insurgency-an-appraisal-of-state-response-51933

[9] PTI, Naxalism Single Biggest Internal Security Challenge: PM, APRIL 13, 2006, 18:17 IST, Last Seen May 10, 2022, https://www.rediff.com/news/2006/apr/13naxal.htm

[10] PTI, Only Bullets Can" t Solve Naxalism, Need a 360-Degree Strategy: Chhattisgarh CM Baghel, Dec 02,2021, 03:42 PM IST, Last Seen May 01, 2022, https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/only-bullets-annt-solv-naxalism-need-a-360-degree-strategy-chhattisgarh-cm-baghel/articleshow/88050006.cms

[11] डॉ. ना.वि. परांजपे, अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं प्रपीड़नशास्त्र,पृष्ठ–111, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, अष्टम संस्करण 2015

[12] डॉ. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, सैंतालीसवाँ संस्करण, 2014, पृष्ठ–335

[13] Neeraj Chauhan, Insurgency-Related Incident Dipped By 80% in N-E State Last Year: MHA Data, March 02, 2021, 03:55 IST, Last Seen May 05, 2022, https://www.hindustantimes.com/india-news/80-reduction-in-insurgency-related-incidents-in-n-e-states-last-year-mha-data-101614676827488.html

[14] भाषा, हताश युवा आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं: अल्ताफ बुखारी, March 07, 2022, 00:42 IST, Last Seen May 09, 2022, https://ndtv.in/india-news/desperate-youth-joining-terrorism-and-getting-killed-altaf-bukhari-2807365

[15] एम.एस.चौहान,अपराधशास्त्र,दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र, सेण्टल्र लॉ एजेंसी, दशम् संस्करण, 2016, पृष्ठ 187

[16] Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, [Hindi], Dec 31, 2015, Last seen May 08, 2022, https://www.indianemplioyees.com/acts-rules/details/juvenile-justice-care-and-protection-of-children-act-2015-hindi

[17] Pankaj Kumar Pandey, Threat: 21% Increase in Cyber Crime Every Year: Rajnath Singh, 14 Jan 2018, 12:26 PM, Last Seen May 09, 2022, https://www.livehindustan.com/national/story-21-percent-increase-in-cyber-crime-every-year-say-rajnath-singh-1748128.html

[18] Pankaj Kumar Panday, Threat: 21% Increase in Cyber Crime Every Year: Rajnath Singh, 14 Jan 2018, 12:26PM, Last Seen May 09, 2022, https://www.livehindustan.com/national/story-21-percent-increase-in-cyber-crime-every-year-say-rajnath-singh-1748128

[19] डॉ. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, सैंतालीसवाँ संस्करण, 2014, पृष्ठ–191,

[20] ए.आई.आर., 2012 एस.सी., 3565

[21] अलका कुमारी, कश्मीर: सुरक्षाबलों के लिए नई चुनौती बन रहा है 'हाईब्रिड' आतंकवादी, ऐसे देता है घटना को अंजाम, Jul 04, 2021, 08:00 PM, Last Seen November 03, 2022, https://www.tv9hindi.com/india/kashmir-hybrid-terrorist-is-becoming-a-new-challenge-for-the-security-forces-this-is-how-they-execute-the-incident-722197.html

[22] Express News Service, Hybrid Militant Arrested in J&K, Arms Recovered, September 15,2022, 5:09:26 PM, Last Seen November 03, 2022, https://indianexpress.com/article/cities/jammu/hybrid-militant-arrested-in-jk-arms-recovered-8152611/

[23] OpIndia Staff, Hybrid Terrorist: What are they and Why are they a Threat to National Security, 23 May, 2022, Last Seen 20 Oct, 2022, https://www.opindia.com/2022/05/hybrid-terrorist-jammu-kashmir-terrorism-national-security/

[24] एम.एस.चौहान,अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र, सेण्टल्र लॉ एजेंसी, दशम् संस्करण 2016, पृष्ठ 28।

[25] Rajnish Singh, India" s Internal Security Remained Under Control in 2020:MHA report, May 02,2022, 13:01 IST, Last Seen May 07, 2022, https://www.aninews.in/news/national/general-news/indias-internal-security-remained-under-control-2020-mha-report2022052130108

[26] कश्मीर से लेकर कोकराझार तक राजनाथ ने सुाक्षा की समीक्षा की, Aug 05, 2016, 08:08 PM IST, Last Seen May 07, 2022, https://zeenews.india.com/hindi/india/kashmir-to-kokrajhar-rajnath-singh-reviews-internal-security/299111